Sixteenth Loksabha

p>

Title: Need to provide the benefit of Credit Linked Subsidy Scheme to allottees of Housing Scheme in Surat Municipal Corporation, Gujarat.

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): मेरे मतक्षेत्र में सूरत महानगरपालिका द्वारा 2014-15 के दौरान एल. आई.जी. आवास योजना पूर्ण की गई थी। जिसमें करीब 8721 लाभार्थियों को आवास प्रदान किए गए।

माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना 17 जून 2015 को लागू की गई थी जिसके तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी का लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है। महा नगरपालिका द्वारा 1 दिसम्बर 2014 को ड्रॉ किया गया था जिसके बाद हरेक लाभार्थी को प्रथम किश्त के रूप में 1,50,000/- रूपये जमा करवाना था एवं बाकी रकम 10 किश्तों में जमा करवानी थी। काफी सारे लाभार्थियों द्वारा लोन लेकर कर्जा करके यह रकम चुकाई गई।

इस योजना के तहत करीब 7500 परिवारों द्वारा 3 लाख से लेकर 6 लाख रूपये तक ऋण लिया गया है। करीब 38 बैंकों द्वारा इसे मंजूर किया गया है। नेशनलाइज्ड बैंकों में इस संबंध में प्रगति हुई नहीं है। तत्पश्चात् महानगरपालिका द्वारा 2296 ई.डब्ल्यू.एस. आवास बनाये गये हैं। एल.आई.जी. आवास 35 से 40 वर्ग मीटर और ईडब्ल्यूएस आवास 20 से 25 वर्ग मीटर के बनाये गये हैं। महानगरपालिका को कोई केन्द्रीय सहायता अभी तक मिली नहीं है। अगर इस योजना को क्रेडिट लिंक सब्सिडी के तहत लाया जाये तो निम्न एवं मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है।

मेरी विनती है कि केन्द्र सरकार द्वारा क्रेडिट लिंक सब्सिडी के तहत इस योजना को सम्मिलित किया जाये
।